

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 95/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00107)

निर्णय दिनांक:- 02-01-2024

1. हाता
2. नाता

पुत्रियों मु. लाला पत्नी बाने खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 6 पीबी
तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

अजय कुमार पुत्र श्री विचित्र कुमार जाति जाट निवासी धीरवास तहसील
तारानगर जिला चूरु।

—रेस्पोंडेन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15-01-2020
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थित:

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 15-01-2020 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट्स का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील पूगल के ग्राम राणीसर के 39 बीघा भूमि निहित थी जोकि अपीलांट्स के पूर्वज कोडा के धारण की खातेदारी भूमि थी, जोकि दौराने चकबन्दी चक 6 पीबी के मुरब्बा नम्बर 5/7 के किला नम्बर 6 ता 8 में 3 बीघा, किला नम्बर 13 ता 18 में 6 बीघा इस प्रकार कुल 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 5/15 के किला नम्बर 6 ता 20 में 14 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 5/23 में किला नम्बर 2 ता 4 तादादी 3 बीघा, किला नम्बर 7 ता 9 में तादादी 3 बीघा, किला नम्बर 11 ता 14 में 4 बीघा, किला नम्बर 17 ता 20 में तादादी 4 बीघा इस प्रकार कुल 38 बीघा 14 बिस्वा भूमि के रूप में पैमूद हुई। उक्त आराजीयात् में से 25 बीघा भूमि अपीलांट्स के पूर्वज कोडा द्वारा दिनांक 25-02-1972 को ही सीतादेवी को बैय कर दी गई थी तथा शेष भूमि चक 6 पीबी के मुरब्बा नम्बर 5/23 के किला नम्बर 2 ता 4 तादादी 3 बीघा, किला नम्बर 7 ता 9 तादादी 3 बीघा, किला नम्बर 11 ता 14 तादादी 4 बीघा एवं किला नम्बर 17 ता 20 तादादी 4 बीघा इस प्रकार कुल 14 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि पर मौके पर मकान आदि बने हुए हैं इस प्रकार अपीलांट्स के परिवार व पशुओं की जीविका का एकमात्र साधन वादगत् भूमि पर कृषि कार्य है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट्स के दादा के कब्जे काश्त में रही है तथा कालान्तर में अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा संवत् 2012 से पूर्व व आज दिनांक तक चला आ रहा है।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि को काफी मेहनत व पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो कोई बयान लिये गये ना ही कोई साक्ष्य व सबूत लिये गये। जबकि अपीलांट्स की माता/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे।


उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर ना तो तनकीयात् कायम की

गई ना ही साक्ष्य ही ली गई। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम की जानी व साक्ष्य जी जानी अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए रिकार्ड क विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जबकि अपने निर्णय में यह खुलासा नहीं किया गया है कि अपीलांट्स/वादी का वाद किस आधार पर खारिज योग्य है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।



अपीलांट का वादगत् भूमि पर विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया गया है। इस प्रकार अपीलांट निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर भी वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उसे नहीं हो पाई। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपने वकील के पास गया और दावे के बारे में जानकारी चाही गई तक अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तुम्हारा दावा तो काफी समय पहले ही निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट वादगत् भूमि बतौर अतिक्रमी काबिज है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।




विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व धारा 188 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15-01-2020 जिसके द्वारा अपीलांट्स की माता/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा खारिज किया गया है के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि के बाबत् निरन्तर लगान अदा किया जाता रहा है। अतः कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट्स वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट्स की माता ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

खातेदारी सनद् जारी करने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।



(4) परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में एकतरफा तौर पर प्रकरण के तथ्यों को अभिलिखित करते हुए बिना बहस सुने वाद खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट्स की माता द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एव संरक्षण हेतु वर्ष 1996 में वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के संबंध दस्तावेजी रिकार्ड, मौके की स्थिति व कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-01-2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे हुए व वादप्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
9. निर्णय आज दिनांक 21/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील कार्यालय
बीकानेर